UP के गन्ना किसानों की फिर से SAP बढ़ाने की मांग

गन्ना किसानों ने बढ़ी लागत का हवाला देकर 327 रुपए क्विंटल SAP करने की मांग की

[ईटी ब्यूरो *मुंबई*]

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने 327 रुपए प्रति क्विंटल के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) की पुरानी मांग फिर से उठाई है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जानकारी दी है। उनका कहना है कि उनकी डिमांड वैज्ञानिक और कृषि संबंधी डेटा पर आधारित है।

किसान जागृति मंच के प्रेसिडेंट सुधीर पवार ने बताया कि शाहजहांपुर के यूपी केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2012-13 सीजन के लिए 228 रुपए प्रति क्विंटल के प्राइस की सिफारिश की थी। पवार के मुताबिक, 'सिफारिशों के आधार पर देखें, तो इस साल डीजल और लेबर कॉस्ट में तेज बढ़ोतरी के कारण हमारी इनपुट कॉस्ट करीब 20 फीसदी बढ़ गई है। इस हिसाब से आगामी सीजन के लिए गन्ने का दाम 273 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है। अगर हम इस प्राइस पर किसानों को 20 फीसदी का प्रॉफिट मार्जिन देंगे, तो एसएपी 327 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार 327 रुपए प्रति क्विंटल का एसएपी घोषित करे।'

हालांकि, राज्य की चीनी मिलें प्रदेश सरकार को पहले ही लिख चुकी हैं कि वे बढ़ते घाटे और बैंकों से वर्किंग कैपिटल नहीं मिलने के कारण गन्ने की 240 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत नहीं दे सकतीं। मिलों ने राज्य सरकार से सब्सिडी भुगतान के रूप में बेलआउट की मांग की है।

> शाहजहांपुर के यूपी केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2012-13 सीजन के लिए 228 रुपए प्रति क्विंटल के प्राइस की सिफारिश की थी

पवार ने कहा, 'चीनी मिलें सरकार पर दबाव बना रही हैं कि अगर एसएपी नहीं घटाया गया या सब्सिडी नहीं मिली, तो कामकाज बंद कर देंगी। वहीं, एसएपी नहीं बढ़ा, तो किसान प्रदर्शन करेंगे।' लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व हेड प्रोफेसर यशवीर त्यागी का कहना है कि चीनी मिलों को इस साल कुछ रियायत मिली है, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे में वे ज्यादा एसएपी दे सकती हैं। प्रोफेसर त्यागी का कहना है, 'पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए लेवी शुगर को हटाकर केंद्र सरकार ने शुगर सेक्टर को डीकंट्रोल किया है, जिससे यूपी की चीनी मिलों को 900 करोड़ रुपए का अलग से फायदा होगा।'

उन्होंने बताया कि चीनी मिलों को परचेज टैक्स कंसेशंस मिला है। साथ ही एथनॉल के दाम बढ़े हैं। इनसे से चीनी मिलों का प्रॉफिट बढ़ेगा।

पेशे से किसान उदय प्रताप सिंह का कहना है कि चीनी मिलों ने अभी तक 2012-13 का बकाया नहीं चुकाया है, जो करीब 2,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि किसानों का पैसा अभी तक चीनी मिलों के पास पड़ा है, जिसका तत्काल आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए।

The Economic Times (Hindi)

3/10/13